

6

अवकाश

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	कर्मचारियों की पाँच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर कार्यवाही	सं० 308/304/XXVII(3)/05, देहरादून, दिनांक-25 जुलाई, 2005	209-210
2	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उपार्जित अवकाश का उपयोग करने हेतु अवकाश पर जाने के पूर्व तथा वापस कार्य पर लौटने के बाद कार्यभार प्रमाणक मरा जाना	सं० 31/XXVII(7)/2006, देहरादून, दिनांक-26 अप्रैल, 2006	211-212
3	प्रसूति अवकाश की सीमा 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में	सं० 250/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक-24 अगस्त, 2009	213-214
4	केन्द्रीय सी०सी०एस० (एल०टी०सी०) रूल्स, 1988 के कतिपय प्राविधानों को जोड़ा/संशोधन के परिचालन विषयक	सं० 284/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक-25 सितम्बर, 2009	215-226
5	महिला सरकारी सेवकों को प्रसूति अवकाश के विषय में स्पष्टीकरण	सं० 360/XXVII(7)/2009, देहरादून, दिनांक-14 दिसम्बर, 2009	227-228

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3

संख्या: 308/304/xxvii(3)/05
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2005

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम-18 में इस आशय का प्राविधान है कि जब तक कि सरकार किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, तब तक किसी सरकारी सेवक को, भारत में बाह्य सेवा से भिन्न अन्यत्र किसी ड्यूटी से पांच वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के पश्चात् चाहे वह अवकाश पर हो या बिना अवकाश के हो, किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पांच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर ऐसे कर्मचारी को सेवा से पृथक करने का प्राविधान है। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधि अनुरूप लगातार अनुपस्थित ऐसे कर्मचारियों की सेवा स्वतः समाप्त नहीं होगी, अपितु ऐसे कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्थापित प्रक्रिया के अधीन स्थायी अथवा उपलब्ध पते पर नियमानुसार आरोप पत्र भेज कर नियमानुसार अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही औपचारिक आदेश द्वारा ऐसे कर्मचारी की सेवा समाप्त किया जाय।

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या : 308(1)/304/xxvii(3)/05, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
4. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल एवं पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार उत्तरांचल।
6. शासन के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
7. शासकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसकी 1000 प्रतियां छाप कर उपलब्ध कराये।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य एकक, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

टी0एन0सिंह
अपर सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल सरकार।

वित्त(वे0 आ0- सा0 नि0)-07

देहरादून, दिनांक: 26 अप्रैल, 2006

विषय:- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उपार्जित अवकाश का उपयोग करने हेतु अवकाश पर जाने के पूर्व तथा वापस कार्य पर लौटने के बाद कार्यभार प्रमाणक भरा जाना।

महोदय,

राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उपार्जित अवकाश का उपभोग करने हेतु अवकाश पर जाते समय तथा अवकाश के उपभोग के उपरांत वापस कार्य पर लौटने पर अपना कार्यभार प्रमाणक भरकर सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराने की नियमों में व्यवस्था है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिस कारण संबंधित अधिकारी के उपार्जित अवकाश पर जाने तथा अवकाश का उपभोग कर कर वापस कार्य पर आने की जानकारी उसके उच्चाधिकारियों को नहीं होती। इससे संबंधित अधिकारी के कार्य को देखने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है।


इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारी उपार्जित अवकाश का उपभोग करने हेतु अवकाश पर जाने के पूर्व तथा अवकाश का उपभोग कर वापस कार्य पर लौटने के बाद अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार प्रमाणक भरकर उसे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराने हेतु प्रस्तुत करें। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। जिस अधिकारी द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: (1)/XXVII(7)/2006 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल, देहरादून ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या: 256/xxvii(7)/2009
देहरादून:दिनांक: 24 अगस्त, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79 दिनांक 4 जून, 1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394 /दस-99-216/79 दिनांक 4 जून, 1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3.उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षको(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0 ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणोत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होंगी।

4.उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेगीं।

5.उपर्युक्त आदेश दिनांक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

6.संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव सचिव।

संख्या: 256(1)/XXVII(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा (से,
24/08/09
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव,
कार्मिक,
उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,
वन, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

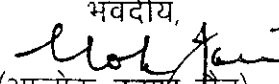
देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2009

विषय:—केन्द्रीय सी0सी0एस0(एल0टी0सी0) रूल्स 1988 में कतिपय प्राविधानों को जोड़ा/संशोधन के परिचालन विषयक।

महोदय,

छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा सी0सी0एस0(एल0टी0सी0) रूल्स 1988 में कतिपय प्राविधानों को जोड़ा/संशोधित किया गया है जैसे परिवार की परिभाषा(नियम-4(डी0), एल0टी0सी0 के प्रकार (नियम-8) इनटाईटलमेन्ट(नियम-12) तथा 10 दिन के उपाजित अवकाश का नकदीकरण आदि के विषय में दिनांक 1-9-2008 में पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 3101/4/2008-ईएटीटी(ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधन प्रभावी किये गये हैं। उक्त तिथि के पूर्व एल0टी0सी0 के निस्तारित दावों को नहीं खोला जाना है। तदनुसार यहां पर भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी व्यवस्था लागू होगी।

2- राज्य सरकार के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक शासनादेश सं0 115/वि0अनु0-3/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर-25 में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा उसी प्रकार अनुमन्य होने की व्यवस्था है, जैसा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाय। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान केन्द्रीय सी0सी0एस0(एल0टी0सी0) रूल्स 1988 में भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय के उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 सितम्बर, 2008 (संलग्न) के द्वारा किये गये समस्त संशोधनों में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में आवंटित तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर दिनांक 1-9-2008 से लागू लागू होंगे।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

F.No. 31011/4/2008- Estt.(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Personnel & Training

New Delhi, the 23rd September, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Sixth Central Pay Commission – Recommendations relating to LTC – Acceptance of.

Consequent upon the acceptance of the recommendations of Sixth Central Pay Commission, it has been decided to make necessary additions/changes in the CCS(LTC) Rules, 1988 as indicated below:-

Rule 4(d) Definition of Family:-

The parents and /or step parents (stepmother and stepfather) who are wholly dependent on the Government employees shall be included in the definition of family for the purpose of LTC, irrespective of whether they are residing with the Government employee or not.

The definition of dependency will be linked to the minimum family pension prescribed in Central Government and dearness relief thereon. The extant conditions in respect of other relations included in the family including married/divorced/abandoned/separated/widowed daughters shall continue without any change.

Rule 8 Types of LTC

Fresh recruits to Central Government may be allowed to travel to their home town along with their families on three occasions in a block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility shall be available to the Government officers only for the first two blocks of four years applicable after joining the Government for the first time. The blocks of 4 years shall apply with reference to the initial date of joining the Government even though the employee changes the job within Government subsequently. The existing blocks will remain the same but the entitlements of the new recruit will be different in the first eight years of service. All other provisions concerning frequency of travel under LTC are retained.

Rule 12 Entitlement

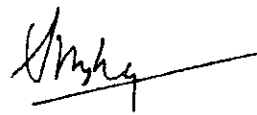
Travel entitlements, for the purpose of official tour/transfer or LTC, will be the same but no daily allowance shall be admissible for travel on LTC. Further, the facility shall be admissible only in respect of journeys performed in vehicles operated by the Government or any Corporation in the public sector run by the Central or State Government or a local body. Air Journey by Private Airlines will however, continue to be admissible as per Ministry of Finance O.M. No. 19024/1/E-IV/2005 dated the 24th March, 2006 and in terms of the orders of DOPT in this regard.

-2/-

Encashment of Earned Leave alongwith LTC

Government officers are allowed to encash ten days earned leave at the time of availing of LTC to the extent of sixty days during the entire career. The leave encashed at the time of LTC will not be deducted from the maximum amount of earned leave encashable at the time of retirement. It is further clarified that where both husband and wife are Government servants, the present entitlement for availing LTC shall remain unchanged, and encashment of leave equal to 10 days at the time of availing of LTC will continue to be available to both, subject to a maximum of sixty days each during the career.

2. **These changes are effective from 1st September, 2008.**
3. The LTC claim pertaining to the period prior to 31st August, 2008 shall be regulated as per rules applicable on the date of journey and LTC claims already settled will not be re-opened.
4. In so far as persons working in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are being issued in consultation with C & A.G. of India.
5. Hindi version will follow.



(P. Prabhakaran)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Tel: 2309 3176

To

All Ministries/Departments of the Government of India (with usual number of copies)

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapathi Bhavan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
6. Central Vigilance Commission, New Delhi
7. Union Public Service Commission, New Delhi.
8. Staff Selection Commission, New Delhi.
9. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
10. All Union Territory Administrations.
11. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
12. All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension.
13. All Officers and Sections of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
14. Website Section, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi.
15. Facilitation Centre, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi – 25 spare copies.
16. 100 spare copies.

F.No.19030/3/2008-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

.....
New Delhi, the 23rd September, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Travelling Allowance Rules-Implementation of the Sixth Central Pay Commission.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decisions taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to Travelling Allowance entitlements, sanction of the President is conveyed to the modifications in the Travelling Allowance Rules as set out in the Annexure to this Office Memorandum in so far as they apply to civilian employees of the Central Government. Separate orders will be issued by the Ministries of Defence and Railways in respect of their personnel.

2. The 'Grade Pay' for determining the TA/DA entitlement is as indicated in Central Civil Service(Revised Pay)Rules 2008.

3. The term 'pay' for the purpose of these orders refer to basic pay as defined in Rule 3(8) of Central Civil Services(Revised Pay) Rules,2008 and includes the revised non-practicing allowance, if any, admissible in addition.

4. In respect of those employees who opt to continue in their pre-revised scales of pay, the corresponding Grade Pay of the pay scales of the post occupied on 1/1/2006 would determine the TA/DA entitlements under these orders. However, for determining the Composite Transfer Grant for such employees, the term pay shall also include, in addition to the basic pay in the pre-revised Scales, stagnation increments, Dearness Pay and NPA as per orders in force on 1/1/2006.

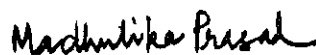
5. These orders shall take effect from 1st September,2008. However, if the Travelling Allowance entitlements in terms of the revised entitlements now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, groups or classes of employees, the entitlements, particularly in respect of mode of travel, class of accommodation, etc., shall not be lowered. They will instead continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time as they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.

6. The claims submitted in respect of journey made on or after 1st September, 2008, may be regulated in accordance with these orders.

7. It may be noted that no additional funds will be provided on account of revision in TA/DA entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements.

8. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India

9. Hindi version will follow.



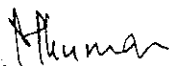
(MADHULIKA P. SUKUL)

Joint Secretary to the Government of India.

To
All Ministries/Departments of the Government of India etc.

Copy to:

- i) All State Governments & Union Territories.
- ii) Governors of all States/Lt. Governors of UTs.
- iii) Comptroller & Auditor General of India and all offices under his Control.
- iv) Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission, Central Vigilance Commission, Deptt. of Personnel (AIS Division), Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt. Commissioner Municipal Corporation of Delhi : and
- v) All Members of Staff Side of the National Council of JCM.



(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG)
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
New Delhi.

**Annexure to Ministry of Finance, Department of Expenditure
O.M.No.19030/3/2008-E.IV dated 23rd September, 2008.**

In supersession of S.R.17 and G.O.I., M.F No.10/2/98-IC& 19030/2/97-E.IV dated 17/4/1998, the following provisions will be applicable with effect from 1.9.2008.

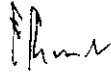
2. Entitlements for Journeys on Tour

A. Travel Entitlements within the Country

Grade Pay (1)	Travel Entitlements (2)
Officers drawing grade pay of Rs.10,000/- and above and those in pay scale of HAG + and above	Business/Club Class by air/AC First class by train
Officers drawing grade pay of Rs.7600, Rs.8700 and Rs. 8900	Economy Class by air/AC First class by train
Officers drawing grade pay of Rs.5400 and Rs.6600.	Economy Class by air/AC II Tier class by train.
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs. 4600 and Rs.4800	AC II Tier class by train.
Officers drawing grade pay below Rs. 4200	First Class/AC III Tier/AC Chair car by train

The revised Travel entitlements are subject to following:-

- (i) In case of places not connected by rail, travel by AC bus for all those entitled to travel by AC II Tier and above by train and by Deluxe/ordinary bus for others is allowed.
- (ii) In case of road travel between places connected by rail, travel by any means of public transport is allowed provided the total fare does not exceed the train fare by the entitled class.
- (iii) Henceforth, all mileage points earned by Government employees on tickets purchased for official travel shall be utilized by the concerned department for other official travel by their officers. Any usage of these mileage points for purposes of private travel by an officer will attract departmental action. This is to ensure that the benefits out of official travel, which is funded by the Government, should accrue to the Government
- (iv) All Government servants are allowed to travel below their entitled class of travel.


(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG)
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
New Delhi.

3. International Travel Entitlement.

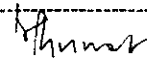
- (i) Cabinet Secretary/Secretary to G.O.I and Equivalent - First Class.
- (ii) Officers drawing grade pay of Rs.10,000 and above and those in pay scale of HAG+ - Business/Club Class
- (iii) Others - Economy Class

C. Entitlement for journeys by Sea or by River Steamer(SR.40)

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
Officers drawing grade pay of Rs.5400/- and above and those in pay scales of HAG+ and above	Highest Class.
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	If there be two classes only on the steamer, the lower class.
Officers drawing grade pay of Rs.2400 and Rs. 2800	If there be two classes only on the steamer, the lower class If there be three classes, the middle or the second class. If there be four classes, the third class
Officers drawing grade pay less than Rs.2400/-	The lowest class.

(ii) Accommodation entitlements for travel between the mainland and the A&N Group of Islands and Lakshadweep Group of Island by ships operated by the Shipping Corporation of India Limited will be as follows:

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
Officers drawing grade pay of Rs.5400 and above and those in pay scales of HAG+ and above	Deluxe Class
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	First / 'A' Cabin class
Officers drawing grade pay of Rs.2400 and Rs. 2800	Second/ 'B' Cabin Class.
Officers drawing grade pay less than Rs.2400.	Bunk Class.


(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG)
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)


D. Mileage Allowance for Journeys by Road :

In supersession of S.R.46 and the Government of India's Order thereunder, the grade pay ranges for travel by public /bus/auto/rickshaw/Scooter/motor cycle, full taxi/taxi/own car is revised as indicated below:

Grade Pay (1)	Entitlement (2)
(i) Officers drawing grade pay of Rs 10,000 and above and those in pay scales of HAG + and above.	Actual fare by any type of public bus including air-conditioned bus. OR At prescribed rates of AC Taxi when the journey is actually performed by AC Taxi OR At prescribed rates for auto rickshaw for journeys by autorickshaw,own scooter motor cycle, moped etc.,
(ii) Officers drawing grade pay of Rs.5400, Rs. 6600, Rs.7600, Rs 8700 and Rs. 8900	Same as at (i) above with the exception that journeys by AC taxi will not be permissible
(iii) Officers drawing grade pay of Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800	Same as at (ii) above.
(iv) Officers drawing grade pay of Rs.2400 and above but less than Rs.4200.	Actual fare by any type of public bus other than air-conditioned bus. OR At prescribed rates for autorickshaw for journeys by autorickshaw/own scooter/ motorcycle/moped etc.
(v) Officers drawing grade pay below Rs.2400.	Actual fare by ordinary public bus only OR At prescribed rates for autorickshaw/ own scooter/ motorcycle/moped etc

(b) Mileage allowance for road journeys shall be regulated at the following rates in places where no specific rates have been prescribed either by the Director of Transport of the concerned State or of the neighbouring States:

- (i) For journeys performed in own car/taxi : Rs.16 per Km
- (ii) For journeys performed by auto rickshaw : Rs.8 per km
own scooter, etc

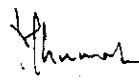

(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG),
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
New Delhi,

(c) The rate of Mileage Allowance for journeys on bicycle, on tour and transfer, is revised from 60 paise to Rs. 1.20 per kilometer.

3. Daily Allowance on Tour

Grade Pay	Daily Allowance
Officers drawing grade pay of Rs. 10,000/- and above and those in pay scales of HAG+ and above	Reimbursement for Hotel accommodation / guest house of up-to Rs. 5000 per day; reimbursement of AC taxi charges of up-to 50 kms. for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 500 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 7600 to Rs. 8900	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 3000 per day; reimbursement of non-AC taxi charges of up-to 50 kms. per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 300 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 5400 to Rs. 6600	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 1500 per day; reimbursement of taxi charges of up-to Rs. 150 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 200 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 4200 to 4800/-	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 500 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 100 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 150 per day.
Officers drawing grade pay of below Rs. 4200/-	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 300 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 50 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 100 per day.

In case of stay/journey on Government ships, boats etc. or journey to remote places on foot/mules etc for scientific/data collection purposes in organization like FSI, Survey of India, GSI etc., daily allowance will be paid at rate equivalent to that provided for reimbursement of food bill. However, in this case, the amount will be sanctioned irrespective of the actual expenditure incurred on this account with the approval of the Head of Department/controlling officer. For journeys on foot, an allowance of Rs.5 per kilometer travelled on foot shall be payable additionally.


(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG)
Ministry of Finance
(Dept. of Expenditure)
New Delhi.

1. T.A. on Transfer.

A. Accommodation and Mileage Allowance Entitlements :

(i) Accommodation and Mileage Allowance entitlements as prescribed at para 2 above, except for **International Travel**, for journey on tour by different modes will also be applicable in case of journeys on transfer. The general conditions of admissibility prescribed in S.R.114 will, however, continue to be applicable.

(ii) The provisions relating to small family norms as contained in para 4(A) of Annexure to M/o Finance O.M. F.No. 10/2/98-IC & F.No. 19030/2/97-EIV dt. 17th April 1998, shall continue to be applicable.

B. Transfer Grant and Packing Allowance :

(i) The Composite Transfer Grant shall be equal to one month's pay as defined in para 3 of this O.M. in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 km from each other.

(ii) In cases of transfer to stations which are at a distance of less than 20kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.

(iii) At present, only one transfer grant is permitted if the transfer of husband and wife takes place within 6 months of each other from the same place to the same place. With effect from the date of implementation of these orders, in cases where the transfer take place within six months, but after 60 days of the transfer of the spouse, fifty percent of the transfer grant on transfer shall be allowed to the spouse transferred later. No transfer grant shall be admissible to the spouse transferred later, in case both the transfers are ordered within 60 days. The existing provisions shall continue to be applicable in case of transfers after a period of six months or more. Other rules precluding transfer grant in case of transfer at own request or transfer other than in public interest, shall continue to apply unchanged in their case.

C. Transportation of Personal Effects

Grade pay (1)	By Train/steamer (2)	Rate per km for transport by road (Rs.per.km) (3)
Officers drawing grade pay of Rs.7600 and above and those in pay scale HAG+ and above	6000 kgs. by goods train/4 wheeler wagon/1 double container.	18.00 (Rs.0.30 per kg per km.)
Officers drawing grade pay of Rs.4200, Rs.4600, Rs.4800, Rs.5400 and Rs. 6600	6000 kgs. by goods Train/4 wheeler wagon/1 single container.	18.00 (Rs.0.30 per kg per km.)
Officers drawing grade pay of Rs.2800	3000 kgs.	9.00 (Rs.0.31 per kg per km)
Officers drawing grade pay below Rs.2800	1500 kgs.	4.60 (Rs.0.31 per kg/per kms.)

M. Kumar
(MAHENDRA KUMAR)
Director (EG)
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
New Delhi.

The rates for transporting the entitled weight by Steamer will be equal to the prevailing rates prescribed by such transport in ships operated by Shipping Corporation of India.

D. Transportation of Conveyance.

Grade Pay (1)	Scale (2)
Officers drawing grade pay of Rs.4200/- and above and those in pay scales of HAG+ and above	One motor car etc. or one motor cycle/scooter, or one horse
Officers drawing grade pay less than Rs.4200/-	One motorcycle/scooter/ Moped, or one bicycle.

5 T.A. Entitlement of Retiring Employees.

A. Transportation of Conveyance.


In partial modification of S.R.147, the expenditure on transportation of conveyance by government servants on their retirement shall be reimbursed without insisting on the requirement that the possession of the conveyance by them while in service at their last place of duty should have been in public interest.

B. Lumpsum Transfer Grant and Packing Allowance.

(i) The composite transfer grant equal to a month's pay last drawn as defined in para 3 of this O.M., may be granted in the case of those employees who, on retirement, settle down at places other than the last station(s) of their duty located at a distance of or more than 20 kms. The transfer incidentals and road mileage for journeys between the residence and the railway station/bus stand, etc., at the old and new station, presently admissible are subsumed in the composite transfer grant and will not be separately admissible.

(ii) As in the case of serving employees, government servants who, on retirement, settle at the last station of duty itself or within a distance of less than 20 kms may be paid one third of the composite transfer grant subject to the condition that a change of residence is actually involved.

6. The TA/DA rates mentioned in para 2 D(b) and (c) (mileage for road journey by taxi/ own car/ autorickshaw/ own scooter/bicycle etc.), para (3) all components of daily allowance on tour including rate of DA for journey on foot) and para 4(c) (rates of transportation of personal effects) of this Annexure, shall automatically increase by 25% whenever Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50% .


(MAHENDRA KUMAR)
Director (G)
Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure)
New Delhi.

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या:360 / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक: 14 दिसम्बर, 2009

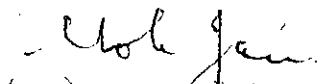
कार्यालय ज्ञाप

विषय:-महिला सरकारी सेवकों को प्रसूति अवकाश के विषय में स्पष्टीकरण।

कार्यालय ज्ञाप संख्या:250 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 के द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन अवकाश तत्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किया गया था।

2- विभिन्न विभागों/श्रोतों से यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि जो सरकारी महिला कर्मचारी उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दि० 24 अगस्त 2009 के निर्गत होने की तिथि को पूर्व व्यवस्थान्तर्गत प्रसूति अवकाश में चल रही हैं उनके विषय में अब परिवर्तित व्यवस्था के बाद किस व्यवस्थान्तर्गत अवकाश अनुमन्य होगा। अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी महिला कर्मिक की अवकाश की अवधि दि० 24 अगस्त, 2009 या इसके पश्चात् पूरी हो गयी और सरकारी सेवक के द्वारा अवकाश के उपयोग के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है ऐसे प्रकरणों को पुर्नउद्घाटित नहीं किया जायेगा और उन्हें पूर्व व्यवस्थान्तर्गत ही अवकाश अनुमन्य होगा, लेकिन यदि महिला कर्मिक उक्त आदेश निर्गत करने की तिथि को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने की तिथि को अवकाश पर चल रही हो और उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण न किया गया हो, तब उसे 135 दिन के स्थान पर 180 दिन का उक्त कार्यालय ज्ञाप दि० 24 अगस्त 2009 की व्यवस्था के अनुसार प्रसूति अवकाश अनुमन्य होगा।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 2009 केवल उक्त सीमा तक सशोधित समझा जाय।

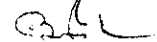

(आलोक कुमार जैसवाल)
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या: (1) / XXVII(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(सचिव वित्त)